ISSN 2249-894X Impact Factor : 3.1402 (UIF) Volume - 5 | Issue - 9 | June - 2016
Review Of Research

'मेक इन इंडिया' पहल का औद्योगिक विकास पर प्रभाव

डॉ. उमेश कुमार शाक्य
प्रवक्ता-अर्थशास्त्र, प्रेम किशन खन्ना राजकीय महाविद्यालय जलालाबाद, शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)

सारांश

मेक इन इंडिया 'Make in India' सितंबर 2014 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी एक महत्वपूर्ण पहल ही जिसका उद्देश्य देश को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना तथा औद्योगिक विकास को गति देना है। इस पहल के अंतर्गत 25 प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा व्यापारिक वातावरण को अधिक अनुकूल बनाने पर विशेष बल दिया गया। मेक इन इंडिया पहल के प्रारंभिक वर्षों में भारत में FDI प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2014 के बाद विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा, जो इस पहल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त, Ease of Doing Business रैंकिंग में भी सुधार देखा गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए गए हैं। यद्यपि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही, जो यह दर्शाता है कि निवेश में वृद्धि का पूर्ण प्रभाव उत्पादन स्तर पर तुरंत दिखाई नहीं देता। इसका कारण यह है कि औद्योगिक विकास एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसमें नीतिगत सुधारों के परिणाम समय के साथ प्रकट होते हैं। मेक इन इंडिया के समक्ष कई महत्वपूर्ण चुनौतियां भी मौजूद हैं। इनमें अवसंरचना की कमी, जटिल श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयाँ, कौशल की कमी, तथा नीतियों के कमजोर क्रियान्वयन जैसी समस्याएं प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी पिछड़ापन भी भारत के विनिर्माण क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन चुनौतियों के समाधान हेतु अवसंरचना में निवेश बढ़ाना, श्रम कानूनों को सरल बनाना, कौशल विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना, नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना तथा Ease of Doing Business में सुधार जारी रखना जैसे महत्वपूर्ण उपायों को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, MSME क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना, तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देना तथा निर्यात-उन्मुख नीतियों को अपनाना भी आवश्यक है। "मेक इन इंडिया" पहल भारत के औद्योगिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उचित रणनीतियों और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से देश को वैश्विक विनिर्माण शक्ति के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है।

बीज शब्द (Keywords) : 'मेक इन इंडिया', औद्योगिक विकास, FDI, विनिर्माण क्षेत्र, भारत, औद्योगिक नीति.

साहित्य समीक्षा

'मेक इन इंडिया' पहल पर प्रारंभिक अध्ययन मुख्यतः इसके संभावित प्रभावों और नीति ढांचे पर केंद्रित रहे हैं-

DIPP (2015) के अनुसार, 'मेक इन इंडिया' का उद्देश्य 25 प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना था, जिनमें ऑटोमोबाइल, रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स प्रमुख थे।

World Bank (2015) की रिपोर्ट के अनुसार भारत की Ease of Doing Business रैंकिंग 142 (2014) से सुधरकर 130 (2016) हो गई, जो सुधारात्मक नीतियों का संकेत है।

KPMG (2015) ने अपने अध्ययन में बताया कि भारत में श्रम लागत कम होने और विशाल बाजार के कारण निवेश की संभावना अधिक है, परंतु अवसंरचना बाधा बनी हुई है।

Reserve Bank of India (RBI, 2016) के अनुसार, 2014-15 और 2015-16 के दौरान भारत में FDI प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो Make in India की सफलता का प्रारंभिक संकेत है।

UNCTAD (2015) की World Investment Report में भारत को शीर्ष FDI गंतव्यों में शामिल किया गया, जो वैश्विक निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

Ahluwalia (2015) ने अपने अध्ययन में कहा कि औद्योगिक विकास के लिए केवल नीतिगत घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।

प्लानिंग कमीशन (2014) के अनुसार, भारत के विनिर्माण क्षेत्र का GDP में योगदान लगभग 15-16% रहा है, जिसे 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था।

इस प्रकार साहित्य समीक्षा से स्पष्ट है कि 'मेक इन इंडिया'के प्रति सकारात्मक अपेक्षाएं थीं, परंतु इसके प्रभावों का आकलन अभी प्रारंभिक अवस्था में था।

शोध पद्धति

इस शोध अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्तियों का प्रयोग किया गया है एवं RBI Bulletin, DIPP Reports, World Bank Reports, UNCTAD, MOSPI (IIP Data) आदि से प्राप्त 2012-2016 (Make in India पूर्व एवं पश्चात तुलना) की अवधि के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्रतिशत विश्लेषण, ट्रेंड विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन तकनीक का प्रयोग किया गया है।

डेटा विश्लेषण

भारत में FDI प्रवाह (USD Billion)

वर्ष	FDI प्रवाह
2012-13	34
2013-14	36
2014-15	45
2015-16	55

Source: RBI, DIPP

Weblink: https://dipp.gov.in

FDI में 2014 के बाद तीव्र वृद्धि दिखाई देती है, जो 'मेक इन इंडिया'के प्रभाव को दर्शाती है।

Industrial Production Index (IIP Growth %)

वर्ष	IIP वृद्धि (%)
2012-13	1.1
2013-14	-0.1
2014-15	2.8
2015-16	2.4

Source: MOSPI

Weblink: http://mospi.nic.in

Ease of Doing Business Ranking

वर्ष	रैंक
2014	142
2015	134
2016	130

Source: World Bank

Weblink: https://www.worldbank.org

डेटा विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 'मेक इन इंडिया'के बाद FDI में तेजी आई। औद्योगिक उत्पादन में भी सुधार हुआ, हालांकि वृद्धि दर अभी भी मध्यम रही। Ease of Doing Business में सुधार से निवेशकों का विश्वास बढ़ा।

समस्याएँ/चुनौतियाँ

'मेक इन इंडिया' पहल भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है, किन्तु मई 2016 तक के अनुभवों से स्पष्ट होता है कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कई संरचनात्मक एवं नीतिगत चुनौतियाँ सामने आई हैं।

सबसे महत्वपूर्ण चुनौती अवसंरचना की कमी है। भारत में बिजली आपूर्ति की अनियमितता, उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, बंदरगाहों की सीमित क्षमता तथा खराब परिवहन नेटवर्क औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता सीधे तौर पर उत्पादन लागत पर निर्भर करती है, और जब आधारभूत सुविधाएँ महंगी एवं अपर्याप्त हों, तो विदेशी निवेशक अन्य देशों जैसे चीन, वियतनाम की ओर आकर्षित हो जाते हैं।

जटिल श्रम कानून दूसरी प्रमुख समस्या हैं। भारत में श्रम कानूनों की संख्या अधिक है और उनका अनुपालन जटिल तथा समय लेने वाला है। उद्योगों को कर्मचारियों की भर्ती और छंटनी में कठिनाई होती है, जिससे वे बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से बचते हैं। यह स्थिति विशेष रूप से श्रम-प्रधान उद्योगों के विकास में बाधा बनती है।

एक अन्य चुनौती भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करना न केवल कठिन है, बल्कि इसमें लंबा समय और कानूनी विवाद भी शामिल होते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों और स्थानीय विरोध के कारण कई परियोजनाएँ विलंबित हो जाती हैं, जिससे निवेशकों का विश्वास प्रभावित होता है।

कौशल की कमी (Skill Gap) भी इस राह में बड़ी बाधा है। भारत में बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से दक्ष श्रमिकों की कमी है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए आवश्यक आधुनिक तकनीकी कौशल का अभाव उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादकता को प्रभावित करता है। इससे 'मेक इन इंडिया'के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण कठिन हो जाता है।

नीतियों का कमजोर कार्यान्वयन भी समस्या है। यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा कई सुधारात्मक नीतियाँ घोषित की गई, किन्तु राज्य स्तर पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी के कारण निवेशकों को कई प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ा।

लालफीताशाही और नौकरशाही मेक इन इंडिया की राह में बाधा है। भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनेक अनुमतियों (clearances) की आवश्यकता होती है, जिससे प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती है। यद्यपि "Single Window System" की अवधारणा प्रस्तुत की गई, परंतु इसका पूर्ण प्रभावी क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो सका था।

एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती वित्तीय बाधाएँ भी है। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सस्ती और सुलभ वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। बैंकिंग प्रणाली में बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों के कारण ऋण वितरण पर भी प्रभाव पड़ा, जिससे औद्योगिक विस्तार सीमित हुआ।

तकनीकी पिछड़ापन भी एक प्रमुख समस्या है। भारत के कई उद्योग अभी भी पारंपरिक तकनीकों पर निर्भर हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। आधुनिक मशीनरी और अनुसंधान एवं विकास में निवेश की कमी इस समस्या को और बढ़ाती है।

नीतिगत अनिश्चितता भी एक महत्वपूर्ण बाधा है। निवेशक दीर्घकालिक स्थिरता चाहते हैं, लेकिन नीतियों में बार-बार बदलाव या स्पष्टता की कमी उनके निर्णयों को प्रभावित करती है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि 'मेक इन इंडिया'पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए इन बहुआयामी चुनौतियों का समाधान अत्यंत आवश्यक है। जब तक इन संरचनात्मक समस्याओं को दूर नहीं किया जाता, तब तक इस पहल के पूर्ण लाभ प्राप्त करना कठिन रहेगा।

सुझाव/उपाय

'मेक इन इंडिया'पहल को प्रभावी और दीर्घकालिक सफलता दिलाने के लिए संरचनात्मक सुधारों, संस्थागत दक्षता और समन्वित प्रयासों की नितांत आवश्यकता है। निम्नलिखित उपाय इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं—

सबसे पहले, अवसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार को बिजली, सड़क, रेल, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा। बेहतर अवसंरचना से उत्पादन लागत कम होगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

श्रम सुधार अत्यंत आवश्यक हैं। श्रम कानूनों को सरल, पारदर्शी और उद्योग-अनुकूल बनाया जाना चाहिए। श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। इससे श्रम-प्रधान उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन में वृद्धि होगी।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण को पारदर्शी, तेज और विवाद-मुक्त बनाने के लिए स्पष्ट नीतियाँ आवश्यक हैं। औद्योगिक पार्क और भूमि बैंक विकसित किए जाने चाहिए, जिससे निवेशकों को आसानी से भूमि उपलब्ध हो सके।

कौशल विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाएं। ITI, पॉलिटेक्निक संस्थानों और निजी क्षेत्र के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए। स्किल इंडिया और डिज़िटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ जोड़कर लागू करना अधिक प्रभावी होगा।

नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। "Cooperative Federalism" के माध्यम से राज्यों को अधिक जिम्मेदारी और प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वे निवेश आकर्षित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

Ease of Doing Business में सुधार को निरंतर जारी रखना होगा। सिंगल विंडो सिस्टम को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, जिससे उद्योगों को सभी अनुमतियाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकें। लाइसेंस और क्लीयरेंस की संख्या कम की जाए और प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाया जाए, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़े।

वित्तीय सुलभता बढ़ाया जाना चाहिए। MSME क्षेत्र को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। बैंकों को उद्योगों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा वैकल्पिक वित्तीय साधनों जैसे वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी को बढ़ावा दिया जाए। इससे नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा ।

तकनीकी उन्नयन पर जोर दिया जाना चाहिए। उद्योगों को आधुनिक मशीनरी और तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश बढ़ाया जाए और विश्वविद्यालयों तथा उद्योगों के बीच सहयोग को मजबूत किया जाए। इससे उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।

निर्यात प्रोत्साहन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। निर्यात-उन्मुख नीतियों को लागू किया जाना चाहिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को मजबूत किया जाना चाहिए। व्यापार समझौतों के माध्यम से नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच बनाई जानी चाहिए।

नीतिगत स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। निवेशकों को स्पष्ट और दीर्घकालिक नीति ढांचा उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे उनका विश्वास बढ़े। कर प्रणाली को सरल और स्थिर बनाया जाए, ताकि उद्योगों को अनिश्चितता का सामना न करना पड़े।

इस प्रकार, यदि उपर्युक्त उपायों को समन्वित और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो 'मेक इन इंडिया' पहल न केवल औद्योगिक विकास को गति दे सकती है, बल्कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

निष्कर्ष

मेक इन इंडिया पहल भारत के औद्योगिक विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप के रूप में उभरकर सामने आई है। सितंबर 2014 में प्रारंभ की गई इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना तथा आर्थिक विकास को गति प्रदान करना था। उपलब्ध आंकड़ों और विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस पहल के प्रारंभिक परिणाम मिश्रित किंतु आशाजनक रहे हैं। FDI प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि इस पहल की एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में सामने आई है। 2014 के बाद भारत में विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ी, जिसका मुख्य कारण नीतिगत सुधार, निवेश-अनुकूल वातावरण तथा वैश्विक स्तर पर भारत की सकारात्मक छवि का निर्माण रहा। यह संकेत करता है कि 'मेक इन इंडिया' ने भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने में प्रारंभिक सफलता प्राप्त की है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में सुधार देखा गया, लेकिन यह वृद्धि अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई। इससे स्पष्ट होता है कि निवेश में वृद्धि के बावजूद उत्पादन क्षमता को पूर्ण रूप से उपयोग में लाने में अभी भी कई बाधाएं मौजूद हैं। यह स्थिति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि केवल निवेश आकर्षित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे प्रभावी उत्पादन और औद्योगिक विस्तार में परिवर्तित करना भी आवश्यक है। Ease of Doing Business रैंकिंग में सुधार भी इस पहल की एक सकारात्मक उपलब्धि रही है। प्रक्रियाओं को सरल बनाने, लाइसेंसिंग प्रणाली में सुधार तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से व्यवसाय स्थापित करना अपेक्षाकृत आसान हुआ है। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है यद्यपि 'मेक इन इंडिया'की सफलता के मार्ग में कई संरचनात्मक चुनौतियां मौजूद हैं। अवसंरचना की कमी, जटिल श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण की समस्याएं, कौशल की कमी, तथा नीतियों के कमजोर क्रियान्वयन जैसे कारक औद्योगिक विकास को सीमित करते हैं। इसके अतिरिक्त, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी पिछड़ापन भी भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, 'मेक इन इंडिया' पहल ने एक मजबूत आधार तैयार किया है, जिस पर भविष्य में औद्योगिक विकास की रणनीतियां निर्मित की जा सकती हैं। सुझाए गए सुधारों को सरकार द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करके दीर्घकाल में अत्यधिक सफल सुनिश्चित की जा सकती है। अंततः निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि 'मेक इन इंडिया' पहल का औद्योगिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, परंतु इसकी पूर्ण क्षमता का लाभ उठाने के लिए निरंतर सुधार और प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है। मेक इन इंडिया पहल भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, किंतु इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण, संस्थागत सुदृढ़ता और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी। 'मेक इन इंडिया' केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक परिवर्तन का एक व्यापक दृष्टिकोण है, जो उचित नीतिगत समर्थन और क्रियान्वयन के माध्यम से देश के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा दे सकता है।

संदर्भ

1. DIPP. (2015). *Make in India Report*. Government of India. https://dipp.gov.in
2. RBI. (2016). *RBI Bulletin*. Reserve Bank of India. https://rbi.org.in
3. World Bank. (2015). *Ease of Doing Business Report*. https://worldbank.org
4. UNCTAD. (2015). *World Investment Report*. United Nations.
5. MOSPI. (2016). *Industrial Statistics*. http://mospi.nic.in
6. KPMG. (2015). *Make in India: Opportunities and Challenges*.
7. Planning Commission. (2014). *Economic Survey*. Government of India.